Assistance for Purchase of Vehicles for Supply of Food Articles Under P.D.S.

3359. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Central Government provide financial assistance to State Governments for the purchase of vans or trucks to be used as mobile fair price shops or as door step delivery vehicles in the RPDS areas;

(b) if so, the details thereof;

(c) what are the year-wise details of the Central financial assistance provided to the State of Gujarat for purchase of vans or trucks for RPDS areas;

(d) the number of vehicles/trucks purchased by Gujarat Government in each year with the help of Central assistance; and

(e) how much Central assitance is likely to be provided to Gujarat in 1996-97?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) and (b) Yes, Sir. Central Government provides financial assistance to States/UTs for purchase of vans/trucks to be used for PDS operations in Revamped Public Distribution System areas especially in remote, hilly, rural and tribal areas. The vehicles are to be used as mobile fair price shops as well as carriers of foodgrains to fair price shops for door-step delivery. The funds under the scheme are provided according to capcity of the vehicles, i.e., Rs. 4/- lakhs are provided for 4 tonner and Rs. 8/- lakhs for 8 or more tonnes capacity in the form of 50% loan and 50% subsidy. Funds are provided on project basis to States/UTs based on proposals received from them, availability of funds, conformity of proposals with the scheme etc.

(c) to (e) Government of Gujarat has not submitted any proposal for sanction of funds under the scheme. Therefore no assistance has been given to Government of Gujarat.

घरेलू उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु प्रयास

3360. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार घरेलू उद्यमशीलता का समर्थन करने और उसे बढ़ावा देने हेतु प्रयास कर रही है:

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रयासों का ब्यौरा क्या है जिनसे इस कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा; और

(ग) इस दिशा में किए गए प्रयासों से कितनी सफलता मिली है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो वर्षों में घरेलू उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में 240 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिससे 6,400 व्यक्तियों को लाभ हुआ। उद्यमशीलता विकास संस्थानों को उनकी अवसंरचना मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई ताकि वे अपने क्षेत्र में उद्यमशीलता विकास पाठ्यक्रमों का आयोजन करने के लिए सुसज्जित हों।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के जरिए, नवयुवकों के बीच घरेलू उद्यमशीलता को बढ़ावा तथा सहायता देने के लिए 3,65,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण/वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ग) अभिप्रेरण अभियानों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए प्रत्याशित उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। सफलता की दर लगभग 30 प्रतिशत होना बताई गई है।

चीनी मिलों के समक्ष आ रही आर्थिक तंगी

3361. **डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष देश में चीनी का रिकार्ड उत्पादन हुआ था और उसे गोदामों में रखे रहने के कारण चीनी मिलों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था;